ttee had submitted its report on 'Industrial Dispersal' which is under examination in consultation with the State Governments and concerned Central Ministries and financial institutions and any change in the existing list of backward areas would depend upon the decisions to be taken on the recommendations of this report.

Cancellation of Non-Implemented Letters of Intent

4135. SHRI CHINTAMANI JENA:
SHRI JAGDISH TYTLER:
SHRI ARJUN SETHI:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether more than half of the letters of intent issued by the industry ministry during 1977-79 have not been implemented so far.

(b) the details regarding the letters issued year-wise and not yet implemented;

(c) whether some letters have been cancelled or lapsed which were issued during above mentioned time ;

(d) if so, the details thereof; and

(e) what measures Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a). No, Sir Only 10 5 per cent of the total number of Letters of Intent issued during 1977 to 1979 lapsed or were cancelled.

(b) to (d). Details of all the Letters of Intent issued are available in Parliament Library in the Monthly News Letter published by the Indian Investment Centre. All Letters of Intent have a validity period of one year, and many are frequently extended while under implementation, on valid justification being advanced. Others lapse or are cancelled, and details of all Letters of Intent cancelled/lapsed are available in the above newsletter.

(e) All administrative Ministries are to review all extent Letters of Intent and if no vaild reasons exist for grant of extension to weed them out by 31st March, 1981.

राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश

4136. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय पूंजी-निवेश बहुत कम है जबकि राज्य में जस्ता, तांबा और अनेक अन्य खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, और

(ख) यदि हां, तो योजना के अन्तर्गत और उसके बाहर पूंजी-निवेश में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

31 मार्च, 1980 को विभिन्न राज्यों को 18161.14 करोड़ रुपये के कुल निवेश (सकल ब्लाक) में से राजस्थान को 337 62 करोड रुपये दिये गये थे । निःसन्देह राजस्थान में मिलने वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग राजस्थान में ही स्थापित किए गए हैं । हिन्दुस्तान जिन्क लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड इसके उदाहरण हैं । हो सकता है कि राज्य के आकार तथा सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों में किए गये निवेश के बीच वस्तुतः कोई सह संबंध दिखाई न देता हो क्योंकि इस्पात, कोयला, पैट्रोलियम आदि क्षेत्र के उद्योग जिनमें भारी निवेश करना होता है, सामान्यतः कच्चे माल के सीत के समीप ही स्थापित किए जाते हैं । इन्हें भी क्षेत्र का सन्तुलित विकास करने पर सदैव ध्यान रखा जाता है और जहां कहीं भी नया निवेश करने संबंधी निर्णय लिए जाते हैं संगत आर्थिक कारणों पर विचार कर लिया जाता है । तथापि छठवीं पंचवर्षीय योजना के

लिए उपलब्ध समस्त साधन स्रोतों को तथा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत की गई योजना-गत प्राथमिकताओं को देखते हुए राजस्थान के लिए राज्य में उपलब्ध खनिज स्रोतों के आधार पर उद्योगों का विकास करने हेतु उपयुक्त बल दिया गया है। राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों में औद्योगिक विकास करने के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में किये गये परिव्यय नीचे बताए गये हैं :---

	रुपये करोड़ों में 1980-85 की योजनावधि में परिव्यय
1. हिन्दुस्तान कापर लि.	
खेतड़ी कापर काम्पलेक्स	34·46
(क) चालू योजनाएं, बदलना एवं नवीकरण	17·01
(ख) नयी योजनाएं अर्थात् स्मेल्टर विस्तार, रिफाइनरी विस्तार, उपोत्पाद संयंत्र अन्वेषणकारी तथा संभारुतापूर्व अध्ययन	16·00
(ग) एस. एण्ड टी. कार्यक्रम	1·45
2. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	99·22
(क) चालू योजनाएं अर्थात् देबरी स्मेल्टर विस्तार, राजपुरा दरीबा खान, मातन फास्फेट खानें	41·75
(ख) नवीकरण एवं बदलाव	23·00
(ग) नयी योजनाएं अर्थात् जाव्माला खानें, बाराइ एक्सपलोरेशन लीच रेसीड्यू ट्रीटमेन्ट प्लान्ट अगूचा बाराइ खान तथा स्मेल्टर काम्पलेक्स सिल्वर मरक्यूरी (चांदी, पारा) रिकवरी प्लान्ट, पायराइट यूटिलाइजेशन प्लान्ट, संभाव्यता अध्ययन तथा अन्वेषण	33·27
(घ) एस. एण्ड टी. कार्यक्रम	1·20
3. पायराइट तथा फारफेट लिमिटेड (नई योजनाएं)	10·50

खनिज पर आधारित उपर्युक्त कार्यक्रम के अलावा, छठी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान स्थित सरकारी क्षेत्र के अन्य केन्द्रीय उद्योगों के लिये भी निम्न प्रकार से परिव्यय निहित है :—

	(करोड़ रुपए में)
1. एच. एम. टी. लि. मशीन टूल प्रभाग अजमेर	1·32
2. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. सांभर साल्ट्स	2·00
3. इन्स्ट्रुमेंटेशन लि., कोटा	3·85
4. हैवी वाटर प्रोजेक्ट, कोटा	13·86
5. आई. डी. पी. एल. के सहयोग से ज्वायन्ट सेक्टर फारमूलेशन यूनिट	0·11

कानून और व्यवस्था की स्थिति

4137. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में निरन्तर बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाये गये हैं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग). विधि और व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है क्योंकि संविधान के अधीन "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय है। केन्द्रीय सरकार ऐसी सहायता और सलाह राज्य सरकारों को देती है जो आवश्यक और उपयुक्त होती है।

राजनीतिक दलों और अन्य वर्गों को राष्ट्रीय एकता परिषद के सामान्य मंच पर